

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर) ।

बृहस्पतिवार, तिथि 7 जुलाई, 1983 ।

विषय-सूची ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

पृष्ठ

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 13, 62, 63, 65, एवं 66,

1—9

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 363, 1692, 1693, 1694,

10—25

1695, 1696, 1698, 1699,

1700, 1703, एवं 1704,

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) —

26—79

दैनिक निबंध ।

81-82

टिप्पणी—जिन मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो रोहतास उद्योग समूह की बीमार घोषित करने का क्या प्रोचित्य है ?

प्रभारी राज्य मंत्री, उद्योग विभाग—उत्तर स्वीकारात्मक है। दिनांक 14 मई, 1983 को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इन इकाई को रूग्ण इकाई के रूप में क्रय कर में छूट एवं बिक्री कर के बदले व्याज रहित ऋण नियमानुसार स्वीकृत किये जाएं।

(2) उत्तर नकारात्मक है। इस उद्योग को रूग्ण इकाई घोषित करने से 2.50 करोड़ रुपये का घाटा सरकार को नहीं होगा बरन उनकी इकाईयों में उत्पादन होने से राज्य सरकार को बिक्री कर के रूप में प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। (सरकार द्वारा जो व्याज रहित ऋण उन्हें दिया जायेगा वह सुरक्षित ऋण होगा तथा उसकी वसूली कम्पनी ही करेगी)।

(3) कम्पनी द्वारा हालिमिया नगर की इकाईयों में समुचित रूप से उत्पादन नहीं हो रहा है, जिसके चलते सरकार की बिक्री कर की क्षति हो रही है। इसमें प्रतिरिक्त यदि उन्हें राज्य सरकार द्वारा वार्षिक सहायता रूग्ण इकाई के रूप में नहीं दी गई, तो संभव है कि उनकी इकाईयों में उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाए कम्पनी को घाटा ही रहा है ऐसी स्थिति में कम्पनी के लगभग 15,000 मजदूर अनियोजित हो जाएंगे, इसीलिए जनकित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें रूग्ण इकाई के रूप में उपर्युक्त वार्षिक सहायता देने का निर्णय लिया है। मैं राज्य सरकार के अलावे भारत सरकार के वित्तीय संस्थानों से कम्पनी के प्राधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु एक बड़ी राशि प्राप्त करेंगे तथा कम्पनी को लाभ में चलायेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

लेखा नियंत्रक श्री झा द्वारा प्रश्न का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

1786. श्री सूर्यनाथरायण यादव—कृषि विभाग, यह बतखाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विपणन पध्द के आ आर० के० झा, लेखा नियंत्रक को बजट में घाटन नहीं रहने के बावजूद भी पदाधिकारी के कर्ज, वाहन की खरीद, विवाह, प्रश्रिम मोटर साइकिल की खरीद हेतु 7,000 रु० का प्रश्रिम स्वीकृत किया गया, जिस मद में श्री झा ने दिनांक 6 नवंबर, 1981 की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रमशः 5000×2000 रु० का दो चेक प्राप्त किया जिसे लेकर श्री झा ने

फ्रेजर रोड स्थित स्टेट बैंक शाखा में अपने खाते में जमा किया है। यदि हां तो सरकार या आर० के० भा, लेखा नियंत्रक द्वारा अधिम के दुरुपयोग के लिए उनके विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमेश भा—बिहार राज्य कृषि विपणन पंचद के मादेश संख्या 944, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 से श्री आर० के० भा, लेखा नियंत्रक को 7,000 रु० की राशि मोटर साईकिल क्रय करने के लिए अधिम के रूप में स्वीकृत की गयी। श्री भा की यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया, फ्रेजर रोड शाखा, पटना, के विरुद्ध 6 नवम्बर, 1981 के चो चक से, क्रमशः 5,000 तथा 2,000, कुल 7,000 रु० का भुगतान किया गया। श्री भा ने राशि प्राप्त कर इसे फ्रेजर रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अपने खाते में जमा किया और बाद में मोटर साईकिल का क्रय किया जिसकी संख्या बी० एच० आर०-5167 है।

1981-82 वर्ष के माध-अधमक में मोटर साईकिल के क्रय मद में 50,000 रु० की राशि स्वीकृत थी, जिसके विरुद्ध उक्त वर्ष में 84,000 रु० की राशि का व्यय हुआ। इसका अनुपरोधन पंचद के निदेशक मंडल की दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 को बैठक में की गयी। उपर्युक्त के आलोक में, अधिम के दुरुपयोग तथा श्री भा के विरुद्ध कोई कार्रवाई का प्रश्न नहीं उत्पन्न है।

कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अधिम के दुरुपयोग के कारण ही दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई है।

1798. श्री अनुराग राम—क्या मंत्री, लघु सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि जिला गिरीडीह अन्तर्गत विरनी प्रखंड के सीमरादाक ग्राम में एक बांध लघु सिंचाई विभाग से वर्ष 1964 में बनी थी;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त बांध 1971 के अप्रत्याशित वर्षात से टूट गया था;
- (3) क्या यह बात सही है कि इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को सूचना देकर बांध पुनः बनाने के लिए 1962 में अनुरोध किया गया था;
- (4) क्या यह बात सही है कि जन प्रतिनिधि के अनुरोध पर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्वाकृति दिसम्बर, 1982 में प्रदान करने के पश्चात् भी पंचसक